सभी स्नेहीजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 13 | प्रति सोमवार, 17 अगस्त 2026 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ के 2161 करोड़ के शराब घोटाले में सनसनीखेज खुलासे

कटघरे में 70 अपराधियों में से कई को बचाने में लगी राज्य की जांच एजेंसियां, करोड़ों की मिल रही रिश्वत

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

भूपेश सरकार के समय हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में कई सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। इस घोटाले में 70 लोग अपराधी हैं। जिनमें से कुछ अपराधियों को राज्य की जांच एजेंसियां बचाने में लगी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि 48 नंबर के अपराधी सिद्धार्थ सिंघानिया को ईओडब्ल्यू सरकारी गवाह बनाने वाली है। जिसके लिए सिद्धार्थ सिंघानिया ने 05 करोड़ की रिश्वत दी है। वहीं घोटाले के प्रमुख अपराधी आशीष सिंह, वैभव मित्तल और आशीष श्रीवास्तव को भी जांच एजेंसियां बचाने में लगी हैं। यह लोग भूपेश सरकार को पैसा कमाकर देते थे। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी सरकार में भी कुछ नेता इन लोगों से पैसा ले रहे हैं। शराब घोटाले में ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी लगभग नामजद 70 लोगों के खिलाफ एवं अन्य के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया, जिस पर शुरूआती दौर में अनेकों लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की गई, जिसमें नामजद लोगों की गिरफ्तारी व उन्हें जेल भेजने तक की कार्यवाही की गई। कुछ समय उपरांत ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर एवं ईडी रायपुर के अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त मामले को ज्ञात/अज्ञात आरोपियों से सांठगांठ एवं उनसे मिलकर इस मामले में संलिप्त लोगों को बचाने, छोड़ने का खेल चालू हो गया। आशीष श्रीवास्तव 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मुख्य कर्ताधर्ता थे। उनको ईओडब्ल्यू/एसीबी रायपुर एवं ईडी रायपुर द्वारा आज दिनांक तक उनसे उपरोक्त अपराध के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई। न ही उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आबकारी विभाग के द्वारा भी उनके विरूद्ध आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियां भी सांठगांठ/मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार कर उससे लगातार बचाया जा रहा है।

(शेष पेज 3 पर)

3

फर्जी IAS बनकर महिला डॉक्टर से 3 लाख की ठगी

6

15 दिन में पुलिस ने किया मामले का खुलासा

7

तिरंगे की छांव में 80वां स्वतंत्रता दिवस

मुख्यमंत्री साय के कार्यकाल में श्रमिक कल्याण से सुशासन को मिली नई पहचान

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में श्रमिकों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। खेतों से लेकर कारखानों तक, निर्माण स्थलों से लेकर छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों तक लाखों श्रमिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में किसी भी सरकार की सफलता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह भी है कि वह श्रमिकों के जीवन, सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को कितना बेहतर बना पाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल को इसी दृष्टि से देखा जाए तो श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों ने शासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है। श्रमिक कल्याण को केवल सहायता राशि या सरकारी योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय उसे सुशासन, पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और त्वरित सेवा वितरण से जोड़ने का प्रयास किया गया है। श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ने भी योजनाओं को अधिक प्रभावी और सरल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट है- सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिक तक बिना अनावश्यक बाधा और देरी के पहुंचे।

श्रमिक कल्याण को बनाया विकास का आधार

राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का दायरा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, मातृत्व, सामाजिक सुरक्षा और कौशल से जुड़े पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार के प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को तकनीक के माध्यम से आसान बनाया गया है। श्रम विभाग द्वारा विकसित यूजर-फ्रेंडली वेबसाइट 'श्रम एव जयते' और मोबाइल एप के माध्यम से श्रमिक ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(शेष पेज 2 पर)

आखिर क्या है दतिया-बांकीपुर की हार का सच?

क्या जनता अब चेहरा चुन रही है, केवल पार्टी नहीं?

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की दतिया और बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में भाजपा को मिली हार ने कई राजनीतिक प्रश्नों को जन्म दिया है। इन परिणामों ने न केवल संबंधित राज्यों की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे, टिकट वितरण की रणनीति और नेतृत्व की निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा की रणनीति कहां चूक गई? क्या यह हार प्रदेश संगठन की विफलता थी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व की परीक्षा थी या फिर केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों का परिणाम? किसी भी चुनावी हार का उत्तर केवल एक व्यक्ति या एक इकाई में तलाशना राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। चुनाव अनेक कारकों का परिणाम होते हैं, जिनमें स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, संगठन की सक्रियता, चुनावी मुद्दे और मतदाताओं की मनोस्थिति शामिल होती है।

चुनाव टिकट के वितरण से ही तय हो गई थी हार

दतिया उपचुनाव में सबसे अधिक चर्चा टिकट वितरण को लेकर हुई। लंबे समय तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा का नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में था। लेकिन यदि पार्टी ने उनके स्थान पर किसी बाहरी और अस्वीकार्य चेहरे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, तो यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से कितना प्रभावी था, इस पर गंभीर समीक्षा अपेक्षित है। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री साय के कार्यकाल में श्रमिक कल्याण से सुशासन को मिली नई पहचान

(पेज 1 का शेष)

इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम करने और सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है। डिजिटल व्यवस्था का यह विस्तार विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो दूरस्थ ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हैं।

पंजीयन और हितलाभ वितरण में बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में श्रमिक पंजीयन और हितलाभ वितरण के आंकड़े सरकार की सक्रियता को दर्शाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया। इसी अवधि में लगभग 17.82 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया और इन पर लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। हितलाभ की राशि सीधे श्रमिकों के खातों में पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी व्यवस्था लागू की गई है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम करने, भुगतान में पारदर्शिता लाने और पात्र हितग्राहियों तक सहायता पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन आंकड़ों का महत्व केवल वित्तीय व्यय में नहीं है। इनके पीछे लाखों श्रमिक परिवारों की जरूरतें, उम्मीदें और जीवन की वास्तविक चुनौतियां जुड़ी हैं। किसी परिवार को आवास सहायता मिलना, किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलना या किसी महिला श्रमिक को मातृत्व सहायता मिलना उसके जीवन में स्थायी बदलाव का आधार बन सकता है।

हर जिले में श्रम प्रशासन की पहुंच

श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच तभी प्रभावी हो सकती है, जब प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत हो। इसी दिशा में राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम कार्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया गया है। पांच नए जिलों में श्रम अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए 20 पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में 10 जिलों में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय और 23 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित हैं। यह पहल प्रशासन को श्रमिकों के और करीब ले जाने वाली है। विशेषकर नए जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर श्रम संबंधी सेवाएं उपलब्ध होने से पंजीयन, शिकायतों के निराकरण और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। विभागीय क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी की गई हैं।

रोजगार के साथ अधिकारों की सुरक्षा

सरकार ने श्रमिक कल्याण के साथ उद्योग और रोजगार के विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। श्रम कानूनों में किए गए विभिन्न संशोधनों के माध्यम से उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ श्रमिक अधिकारों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। दुकानों एवं स्थापना अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, महिला श्रमिकों के लिए रात्रिकालीन कार्य की सुविधा और फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने जैसे निर्णयों को इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा सकता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ कामगारों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार की नीति में इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास दिखाई देता है।

श्रमिकों के लिए 24 घंटे सहायता

श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्रों की स्थापना भी महत्वपूर्ण पहल है। सहायता केंद्र को 24 घंटे और सातों दिन संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही राजधर में मोबाइल शिविरों के माध्यम से श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। मोबाइल शिविरों की व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिकों को मिल सकता है, जिन्हें छोटी-छोटी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए दूर स्थित कार्यालयों तक जाना पड़ता है। सरकार जब सेवा को श्रमिक के घर और कार्यस्थल के करीब ले जाती है तो इससे न केवल समय और खर्च बचता है, बल्कि शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है।

आवास और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

श्रमिक परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत आवास सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। आवास किसी भी परिवार के लिए केवल एक भौतिक सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान का आधार होता है। इसलिए श्रमिकों को आवास के लिए सहायता देना उनके जीवन की बुनियादी जरूरत को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति, शिक्षा सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल देने का प्रयास किया गया है। संकट की परिस्थितियों में ऐसी सहायता परिवार को आर्थिक असुरक्षा से उबरने में मदद करती है।

महिला श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा की पहल

श्रमिक कल्याण का कोई भी मॉडल तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसमें महिला श्रमिकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व न मिले। भिलीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता प्रदान की गई है। मातृत्व के समय आर्थिक सहायता महिला और उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनती है। इसके अलावा महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थल से जुड़े अवसरों को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सकते हैं। यह बदलाव केवल महिला के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

पांच रुपये में पौष्टिक भोजन

शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना भी श्रमिक हित से जुड़ी उल्लेखनीय पहल है। इसके माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को मात्र पांच रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्माण और अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना उनके स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना श्रमिक कल्याण को केवल आर्थिक सहायता के नजरिए से देखने के बजाय उनके दैनिक जीवन की वास्तविक जरूरतों से जोड़ती है। यही दृष्टिकोण कल्याणकारी शासन को अधिक मानवीय बनाता है।

शिक्षा और अगली पीढ़ी के सपनों को सहारा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की श्रमिक कल्याण नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष श्रमिक परिवारों के बच्चों का भविष्य भी है। मेधावी शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति और निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग जैसी योजनाओं के माध्यम से श्रमिक परिवारों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देने का प्रयास किया गया है। शिक्षा में निवेश वास्तव में अगली पीढ़ी के भविष्य में निवेश है। यदि श्रमिक का बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाता है तो इसका प्रभाव पूरे परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस दृष्टि से श्रमिक कल्याण को शिक्षा से जोड़ना दूरगामी परिणाम देने वाला कदम है।

आंकड़ों से आगे विश्वास की कहानी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ढाई वर्ष के कार्यकाल में श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रयासों को केवल योजनाओं और आंकड़ों के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इन योजनाओं का वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब किसी श्रमिक परिवार को संकट के समय आर्थिक सहायता मिलती है, किसी महिला को मातृत्व के दौरान संबल मिलता है, किसी परिवार को अपना घर बनाने में मदद मिलती है या किसी श्रमिक के बच्चे को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का अवसर मिलता है। यही वह बिंदु है जहां सरकार की नीतियां कागज से निकलकर आम आदमी के जीवन से जुड़ती हैं। तकनीक, पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के साथ योजनाओं की पहुंच बढ़ाना इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।

आखिर क्या है दतिया-बांकीपुर की हार का सच?

(पेज 1 का शेष)

किसी भी राजनीतिक दल के लिए टिकट वितरण केवल संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि वह मतदाताओं के प्रति पार्टी के संदेश का भी माध्यम होता है।

हार पर क्या केवल कार्यकर्ता ही जिम्मेदार?

दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही को लेकर उठ रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उम्मीदवार चयन का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का था। ऐसे में यदि टिकट चयन की प्रक्रिया में नितिन नबीन, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो हार के बाद केवल स्थानीय संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराना कितना उचित है?

अनुभवहीन नेताओं को बनाया प्रभारी और सहप्रभारी

वहीं उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, सांसद एवं सहप्रभारी राहुल कोठारी, प्रदेश महामंत्री, भाजपा की भी हार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। राहुल कोठारी अनुभवहीन नेता हैं। वह दतिया के समीकरण के विषय में क्या जानते हैं। देखा जाता है कि चुनाव प्रभारी की बड़ी अहमियत होती है। पूरा प्रबंधन इनके ही हाथ में होता है। बीजेपी ने यहां पर चूक की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि शीर्ष नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी के नाम पर अंतिम मुहर लगाई थी, तो चुनाव परिणाम की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी भी शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। केवल मंडल, जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई या संगठनात्मक बदलाव की चर्चा यह संदेश देती है कि निर्णय ऊपर लिए जाते हैं, लेकिन जवाबदेही नीचे तय होती है। अब आवश्यकता इस बात की है कि टिकट चयन, चुनावी रणनीति और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। यदि समीक्षा केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित रही और शीर्ष स्तर के निर्णयों पर सवाल नहीं उठे, तो संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और भविष्य के चुनावों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

उम्मीदवार की स्वीकार्यता को मिला मतदान

दतिया और बांकीपुर दोनों राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण अलग हैं, लेकिन दोनों चुनावों से एक समान संदेश निकलता दिखाई देता है। वह यह कि आज का मतदाता पहले की तुलना में अधिक जागरूक और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला है। वह केवल दल के नाम पर मतदान करने के बजाय उम्मीदवार की स्वीकार्यता, उपलब्धता, कार्यशैली और स्थानीय जुड़ाव को भी महत्व देता है। यदि किसी क्षेत्र में मतदाताओं को लगता है कि उम्मीदवार उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो वे पार्टी के पारंपरिक समर्थन के बावजूद अपना निर्णय बदल सकते हैं।

कांग्रेस की रणनीति पर लगी जनता की मुहर

भारतीय राजनीति में दल और नेतृत्व दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि उम्मीदवार की विश्वसनीयता और स्थानीय पहचान का महत्व पहले की तुलना में और अधिक बढ़ा है। यही कारण है कि कई बार मजबूत दल भी कमजोर उम्मीदवार के कारण चुनाव हार जाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत कमजोर दल मजबूत स्थानीय चेहरे के दम पर जीत दर्ज कर लेते हैं। इन दोनों उपचुनावों में कांग्रेस की सफलता को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि कांग्रेस ने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके पीछे केवल भाजपा की कमजोरियां ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति, स्थानीय संगठन की सक्रियता, उम्मीदवार चयन और नेतृत्व की मेहनत भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। किसी भी चुनावी जीत को केवल विरोधी दल की हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सफल चुनाव अभियान में संगठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की विश्वसनीयता और मतदाताओं तक प्रभावी पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और स्थानीय नेतृत्व ने यदि लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और जनता के बीच संवाद स्थापित किया, तो इसका सकारात्मक प्रभाव चुनाव परिणामों में दिखाई देना स्वाभाविक है।

भाजपा के सामने हैं अब बड़ी चुनौती

भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इन हारों को सामान्य उपचुनावी परिणाम मानकर नजरअंदाज करती है या इन्हें गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में स्वीकार करती है। इतिहास बताता है कि उपचुनाव कई बार भविष्य के बड़े चुनावों की दिशा का संकेत देते हैं, हालांकि हर उपचुनाव का परिणाम विधानसभा या लोकसभा चुनावों में उसी रूप में दोहराया जाए, यह आवश्यक नहीं है। फिर भी यदि लगातार कुछ क्षेत्रों से असंतोष के संकेत मिलते हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए उनका गंभीर विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

फर्जी IAS बनकर महिला डॉक्टर से ₹3 लाख की ठगी

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जीवनसाथी डॉट कॉम पर महिला चिकित्सक से संपर्क कर खुद को डॉक्टर और IAS अधिकारी बताकर करीब 3 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को नरसिंहपुर पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय कुमार निवासी भदोही (उत्तर प्रदेश) ने खुद को MBBS, MD, DM डिग्रीधारी तथा UPSC चयनित मध्यप्रदेश कैडर का IAS अधिकारी बताते हुए धार में SDM पद पर पदस्थ होने का झूठा दावा किया था। उसने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध होने की बात कहकर महिला चिकित्सक का विश्वास जीता और सहायता के नाम पर रकम हासिल की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने गांव और परिजनों को भी खुद को IAS अधिकारी बताता था। वह AI तकनीक से फोटो एडिट कर वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक संस्थानों के साथ अपनी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया

पर डालता था। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वाराणसी में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है। किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि या फर्जी प्रोफाइल की सूचना तत्काल पुलिस अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

देश के विभाजन का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. टेहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को नमन करते हुए कहा कि देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विभाजन की विभीषिका को इतिहास का काला अध्याय तथा दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाकर विभाजन के साथ विस्थापन का दर्द झेला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश जब आजादी का जश्न मना रहा था वहीं देश के विभाजन का भी दर्द हमें सहना पड़ा। भारत के लिए यह घटना किसी विभीषिका से कम नहीं थी। वर्ष 2021 में इसी दर्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से यह दिन मनाया जा रहा है, ताकि हम अपने उन लाखों सेनानियों व परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन उन सभी सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने भारत माँ के लिए बलिदान दिया। भारत के बंटवारे ने सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश को स्वतंत्र कराने वाले और देश के विभाजन की यातनाएं झेलने वाले मां भारती के प्रत्येक सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। यह दिवस हमारी भावी पीढ़ी को इतिहास की उस विभीषिका से परिचित कराता रहेगा।

(पेज 1 का शेष)

कटघरे में 70 अपराधियों में से कई को बचाने में लगी राज्य की जांच एजेंसियां, करोड़ों की मिल रही रिश्वत

सिंडीकेट के माध्यम से होता था पैसों का लेन-देन

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अनवर ढेबर, अरूणपति त्रिपाठी विशेष सचिव, आबकारी विभाग एवं एमडी छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के साथ सिंडिकेट के रूप में कार्य कर अनवर ढेबर के सहयोगी विकास अग्रवाल, अरविंद सिंह, संजय दीवान, देशी शराब आसवनी मालिक तथा जिला मुख्यालयों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में मदिरा की बिक्री में अवैधानिक कमीशन की उगाही कर तथा बिना हिसाब के मदिरा की शासकीय मदिरा दुकानों में सप्लाई कर लगभग 2161 करोड़ रू. की अवैध कमाई की गयी है। इसी अवैध रकम से उच्च पदस्थ अधिकारी अनिल टुटेजा, अरूणपति त्रिपाठी एवं अनवर ढेबर द्वारा बहुत सारी अचल संपत्ति अर्जित की गयी है, जिसे ईडी द्वारा प्राविजनल अटैचमेंट आदेश क्रमांक 03/2023 के तहत अटैच भी किया गया है। ईडी द्वारा आयकर विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर ईसीआईआर क्रमांक 11/2022 पंजीबद्ध कर जांच की गयी तथा पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 3 एवं 4 के तहत कार्यवाही कर अनवर ढेबर, अरूणपति त्रिपाठी एवं अन्य को विशेष न्यायालय (पीएमएलए एक्ट) रायपुर में पेश कर रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। जिसका प्रकरण लंबित है। सूत्रों से प्राप्त प्रमाणिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में देशी मदिरा के निर्माणकर्ता आसवनी मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट प्रायवेट लिमिटेड एवं वेलकम डिस्टलरिस प्रायवेट लिमिटेड है, जिन्हें राज्य में देशी मदिरा प्रदाय करने का लाईसेन्स प्राप्त है। अनवर ढेबर द्वारा अनिल टुटेजा से अपने पारिवारिक संबंध एवं राजनीतिक प्रभाव का लाभ लेते हुए सीएसएमसीएल के प्रबंध संचालक अरूणपति त्रिपाठी के साथ मिलकर शराब निर्माता आसवनी से शराब निर्माण कर उपलब्ध कराने के रेट में बढ़ोतरी करने जिसके एवज में आसवनी मालिकों से लाखों रूपयों का अवैध कमीशन प्राप्त किया गया। ईडी ने इसे पार्ट-ए के भ्रष्टाचार के रूप में दर्शित किया है कि व्यवस्था के समानांतर नयी व्यवस्था बनाकर आसवनी संचालकों से बिना रिकार्ड के देशी मदिरा इसी तरह देशी मदिरा के सप्लाई हेतु राज्य में बनायी गयी तासकीय शराब दुकानों का निर्माण कराकर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शासकीय मदिरा दुकानों के माध्यम से पृथक से बिक्री कराकर उससे करोड़ों रूपयें की अवैध कमाई की गयी है। इस कृत्य में आसवनी मालिकों, बोतल सप्लाईकर्ता एजेंसी, डुप्लीकेट होलोग्राम प्रदायकर्ता एजेंसी, बी-पार्ट की शराब बिक्री के पैसे कलेक्ट करने वाली एजेंसी, आबकारी विभाग के अधिकारी, अरूणपति त्रिपाठी के संलिप्त रहे हैं। ईडी द्वारा इसे बी-पार्ट के कमीशन के रूप में आरोपित किया गया है। इस प्रकार के विकय वर्ष 2019-2020, 2020-21, 2021-2022 में किया गया। इस अवैध मदिरा की बिक्री से प्राप्त अवैध वसूली राशि का कार्य विकास अग्रवाल के माध्यम से किया जाता था, जो अनवर ढेबर एवं अरूणपति त्रिपाठी को इसकी जानकारी देता था। सूत्रों के अनुसार प्रतिमाह लगभग 200 ट्रक, जिसमें प्रति ट्रक लगभग 800 मदिरा के केस होते थे जो कि शराब निर्माताओं द्वारा सिंडीकेट को प्रदान किये जाते थे। सूत्रों के अनुसार 2019-2020 में अवैध मदिरा 560 रू. प्रति प्रकरण के हिसाब से शराब निर्माताओं से प्राप्त की जाती थी, जिसे 2880 रू. एमआरपी पर बेचा जाता था, जो बाद में 3880 रूपये तक बेचा गया। इस सम्पूर्ण कार्य के लिए शराब निर्माताओं को 560-600 रूपये प्रति केस तथा आबकारी अधिकारियों को लगभग 150 रू. प्रति केस दिया जाता था। शेष सम्पूर्ण राशि अनवर ढेबर द्वारा विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू के माध्यम से ली जाती थी। सूत्रों के अनुसार इसी राशि का लगभग 15 प्रतिशत शेयर अनिल टुटेजा एवं अनवर ढेबर स्वयं रख लेते थे तथा शेष हिस्सा राजनेताओं को बाँट देते थे। राशि लेने-देने का कार्य भी अनवर ढेबर एवं उसके अधीनस्थ लोगों द्वारा किया जाता था।

ननकीराम ने लिखा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को पत्र

पूर्वमंत्री ननकीराम ने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर आशीष श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त रायपुर एवं सिद्धार्थ सिंघानिया को एजेंसियों द्वारा बचाने एवं क्लीनचिट देने पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। उन्होंने लिखा है कि निर्देश के बाद भी ईओडब्ल्यू/एसीबी एवं ईडी द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। और अपराधियों को बचाया जा रहा है।

शराब घोटाले के मुख्य आरोपी

डुप्लीकेट होलोग्राम लगी मदिरा विक्रय का कारोबार प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, गरियाबंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बेमेतरा एवं रायगढ़ जिलों में किया जाता रहा है। डुप्लीकेट होलोग्राम लगी मदिरा की सप्लाई में आबकारी विभाग के तत्समय पदस्थ जनार्दन कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रायपुर, अनिमेष नेताम, डिप्टी कमिश्नर आबकारी धमतरी, विजय सेन शर्मा, डीप्टी कमिश्नर आबकारी, महासमुंद, प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी, रामकृष्ण मिश्रा, सहायक आबकारी आयुक्त, विकास गोस्वामी, सहायक आबकारी आयुक्त, इकबाल खान, जिला आबकारी अधिकारी, नितिन खोंडुजा, जिला आबकारी अधिकारी, नवीन प्रताप सिंह तोमर, सहायक आयुक्त आबकारी, मंजुश्री कसेर, जिला आबकारी अधिकारी, सौरभ बख्शी, सहायक आयुक्त आबकारी, दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त आबकारी, आशीष श्रीवास्तव, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी मुख्यालय, अशोक सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, मोहित जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी, नीतू नोतानी, उपायुक्त आबकारी, रविश तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, गरीबपाल दर्दी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, नोहर सिंह ठाकुर, आबकारी अधिकारी, सोनल नेताम, सहायक आयुक्त की संलिप्तता पायी गयी है। उक्त संपूर्ण सिंडीकेट के मुख्य भूमिका सीएसएमसीएल के तत्कालीन प्रबंध संचालक अरूणपति त्रिपाठी द्वारा की गयी है, जिनके द्वारा आसवनी मालिकों की होटल वेनिंगटन में अनवर ढेबर से मुलाकात कराकर मदिरा के रेट में बढ़ोतरी किये जाने उसके एवज में भारी मात्रा में कमीशन देने हेतु दबाव बनाया गया। मेसर्स प्रीज्म होलोग्राम एण्ड सिक्योरिटीस प्राई. लिमिटेड के विधु गुप्ता से डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई हेतु योजनाबद्ध तरीके से टेण्डर दिलवाकर पूर्व में इस्तेमाल हो चुके होलोग्राम के नंबर पर ही डुप्लीकेट होलोग्राम तैयार कराकर उसके अधीनस्थ दिपक दुबारी से सहायक आयुक्त आबकारी जनार्दन कौरव के माध्यम से आसवनी मालिकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करायी गयी। अरूणपति त्रिपाठी को उपरोक्त अपराधिक कृत्य से करोड़ों की अवैध राशि प्राप्त होने की जानकारी मिली है, जिसमें से लगभग 20 करोड़ के अवैध रकम डुप्लीकेट होलोग्राम युक्त देशी मदिरा बिक्री से कमीशन बतौर प्राप्त हुयी है। सचिव निरंजनदास के कार्यकाल में विदेशी मदिरा निर्माताओं से रिश्वत उगाही हेतु तत्कालीन सहायक आयुक्त, आबकारी, मंजुश्री कसेर, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, सौरभ बख्शी, तत्कालीन सहायक आयुक्त, दिनकर वासनिक, तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, आशीष श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी, श्रीमती नीतू नोतानी, उपायुक्त, रविश तिवारी, तत्कालीन सहायक आयुक्त आबकारी, गरीबपाल दर्दी, आबकारी अधिकारी, नोहर सिंह ठाकुर, आबकारी अधिकारी, श्रीमती सोनल नेताम, सहायक आयुक्त, आबकारी विभाग, अरविंद सिंह, अनुराग द्विवेदी, मेसर्स अनुराग ट्रेडर्स, अमित सिंह मेसर्स अदीप एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड, नवनीत गुप्ता, श्रीमती पिंकी सिंह, प्रोप्राईटर अदिप एम्पायर्स, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, त्रिलोक सिंह, ढिल्लन, मेसर्स ढिल्लन सिटी मॉल प्राईवेट लिमिटेड, यश टुटेजा, निवासी कटोरा तालाब रायपुर, नितेश पुरोहित, गिरीराज होटल, रायपुर, यश पुरोहित, गिरीराज होटल, रायपुर, अभिषेक सिंड डायरेक्टर मेसर्स नेक्सजेन पॉवर इंजीटेक प्राईवेट लिमिटेड, मनीष मिश्रा, मेसर्स नेक्सजेन पॉवर इंजीटेक प्राईवेट लिमिटेड, संजय कुमार मिश्रा, सीए मेसर्स नेक्सजेन पॉवर इंजीटेक प्राईवेट लिमिटेड, अतुल कुमार सिंह ओम साई, बेयरेजेस्ट प्राईवेट लिमीटेड, मुकेश मनचंदा, ओन साई, बेवरेजेस प्राईवेट लिमिटेड, विजय भाटिया, भिलाई, आशीष सौरभ केडिया, मेसर्स दिशिता वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स भाटिया वाईन एवं मर्चेंटस प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स वेलकम डिस्टलरीस, सिद्धार्थ सिंघानिया, मेसर्स सुमित फैसलिटीस लिमीटेड एवं टॉप सिक्योरिटीस फैसलिटीस मैनेजमेंट, बच्चा राज लोहिया मेसर्स इगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड एवं पार्टनर, मेसर्स अलर्ट कमाण्डो प्राईवेट लिमिटेड एवं पार्टनर, अमित मित्तल, मेसर्स ए-टू-जेड प्राईवेट लिमिटेड एवं सहयोगी, उद्यत्राव मेसर्स ए-टू-जेड प्राईवेट लिमिटेड का मैनेजर, मेसर्स प्राईम वन वर्क फोर्स, लक्ष्मीनारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल निवासी भिलाई, विधु गुप्ता, प्रीज्म होलोग्राफी एवं सिक्योरिटीस प्रा.लि., दीपक दुआरी, दिपेन चावड़ा, मेसर्स प्राईम डेवलपर्स, मेसर्स ए देबर बिल्डकॉन, मेसर्स ए.जे.एस. एग्रोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड सफायर इस्पात के मालिक उमेर ढेबर एवं जुनैद ढेबर, अख्तर ढेबर, मेसर्स जगदम्बा इंटरप्राईजेस, अशोक सिंह, सुमित मलो, रवि बजाज, विवेक ढांड, कांग्रेस के पदाधिकारीगण, अन्य आबकारी अधिकारीगण, विकास अग्रवाल के साथीगण एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण में प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 12 घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
कृषि विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
गांव हमारी धरोहर हैं

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
हरि शर्मा
नर्मदापुरम (म.प्र.)
जीवन में अपना आवास जरूरी

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
विपणन विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
स्वच्छ जिला, स्वच्छ राज्य, स्वच्छ देश

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
लोक निर्माण विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
निर्माण उच्च गुणवत्ता का आधार

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
खनिज विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
प्रकृति हमारे जीवन का आधार है

आप सबको आजादी के इ
शुभकामनाएं। 140 करोड़ दे
विकसित भारत। विकसित भा
ना हम झुकेंगे, और 2047 में f

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
जल संसाधन
नर्मदापुरम (म.प्र.)
जल है तो कल है

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
आबकारी विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
मिलावट से बचें

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
नगर पालिका परिषद
नर्मदापुरम (म.प्र.)
समस्त करो का भुगतान समयावधि में करें

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
नर्मदापुरम (म.प्र.)
यातायात के नियमों का पालन करें
कृपया हेलमेट का प्रयोग करें

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
वन विभाग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
पेड़ लगाएं जीवन बचाएं

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
जनपद परिषद
नर्मदापुरम (म.प्र.)
गांव हमारी धरोहर

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
15 August
कृषि उपज मंडी
नर्मदापुरम (म.प्र.)
एक बीज बनता है पौधा

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
रेशम उद्योग
नर्मदापुरम (म.प्र.)
धागा हर कड़ी जोड़ता है

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें...
जिला शिक्षा केन्द्र
नर्मदापुरम (म.प्र.)
जल ही जीवन है

सभी देशवासियों को
80 वें स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ

स महान पर्व की अनेक-अनेक
शवासियों का एक ही मंत्र है-
रत बनाने के लिए ना हम रुकेंगे,
विकसित भारत बना कर रहेंगे।
- नरेन्द्र मोदी

CBC 22201/13/0021/2627

सम्पादकीय

80वें स्वतंत्रता दिवस पर नए भारत का संकल्प

स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने का भी दिन है। 15 अगस्त 2026 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इस बार का समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसकी प्रमुख भावना 'युवा शक्ति से विकसित भारत@2047' और 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष के स्मरण से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री के संबोधन का केंद्रीय विचार स्पष्ट था- भारत को अब छोटे लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक, विनिर्माण, कृषि, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा को विकास के प्रमुख आधारों के रूप में रेखांकित किया। यह दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता के आठ दशक पूरे करने की दिशा में बढ़ता भारत अब केवल विकासशील देश की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता। भाषण में प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में देश में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। विनिर्माण, डिजिटल आधारभूत ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नवाचार और युवाओं के सशक्तीकरण को उन्होंने भारत की बदलती तस्वीर के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। यह संदेश वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि किसी भी बड़े राष्ट्र के लिए आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता उसकी रणनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं को भारत के भविष्य का निर्माता बताया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कौशल विकास की घोषणा की। अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को एआई का प्रशिक्षण देने की घोषणा इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में शिक्षा और रोजगार की दिशा तेजी से बदलने वाली है। गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग की पहल भी शिक्षा के अवसरों को अधिक सुलभ बनाने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और रोजगार से उसका संबंध कितना मजबूत बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के भाषण में 'सप्तधारा' की अवधारणा भी सामने आई, जिसमें विनिर्माण, कृषि, तकनीक और नवाचार, तेज संपर्क एवं आधारभूत संरचना, रक्षा, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था तथा भारत की सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्रों को विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में रेखांकित किया गया। यह व्यापक दृष्टिकोण बताता है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि उत्पादन, पर्यावरण, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक प्रभाव को एक साथ आगे बढ़ाने से जुड़ा है। हालाँकि, किसी भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण का मूल्यांकन केवल घोषणाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन से होना चाहिए। विकास की चमक के साथ बेरोजगारी, ग्रामीण आय, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता और पर्यावरण जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। इसलिए विकसित भारत का सपना तभी सार्थक होगा, जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और अवसरों में समानता बढ़े।

80वें स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत ने अतीत की उपलब्धियों पर रुकने के बजाय भविष्य की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री का संबोधन महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति पर केंद्रित रहा। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन संकल्पों को ठोस नीतियों, पारदर्शी शासन और जनभागीदारी के माध्यम से जमीन पर उतारा जाए। स्वतंत्रता की असली सार्थकता तभी होगी, जब भारत आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के साथ-साथ न्यायपूर्ण, समावेशी, शिक्षित और संवेदनशील राष्ट्र भी बने।

15 दिन में पुलिस ने मामले का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेजा

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिमरनी। ग्राम डगांवानीमा में किसान रूपसिंह जाट के यहां 15 दिन पहले रात के समय करीब 60 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसे पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में नर्मदापुरम के सिवनी मालवा थानाक्षेत्र के जामुनिया गांव के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे चोरी का माल बरामद किया गया है। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है। चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को नोटिस तामिल कराया गया है। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई थीं। मुखबिर तंत्र, साइबर सेल, तकनीकी दक्ष सभी की मदद और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर सारी कड़ी जोड़ी गई। घटनास्थल सहित आसपास की कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साइबर सेल की भी मदद ली गई। सभी कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने नागरिकों से अपील है कि वे रात में सोते समय खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर सोएं, जिससे ऐसी वारदातों से बचा जा सके।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

किता भंडारी के परिवार से 2 दिन पहले मिला। चार साल बीत चुके है, लेकिन आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे है - अपनी बच्ची के खिलाफ एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी कोई माफी नहीं।
सिर्फ 19 साल की अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी जहां एक "VIP" मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबो कर उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिंसा और डुबोने के सबूतों की पुष्टि भी की।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

प्रदेश के अशोकनगर जिले के महोली गांव में महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा हटाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रशासन के इस कृत्य के खिलाफ ग्रामीणों एवं लोधी समाज में नाराजगी है।
क्या प्रशासन को इतनी समझ नहीं है कि उनके कृत्य से समाज में गुस्सा भड़केगा।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

प्रदूषण मुक्त भारतः हमारी नई आज़ादी

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश ने इन सालों में हर नए क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विकास की दौड़ में हम विकसित देशों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। भारत आज विश्व शक्ति बनने के सपने देख रहा है लेकिन इन सबके बीच बहुत कुछ है जो हम खो रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में हम नई नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हमारे जंगल खत्म हो रहे है, हमारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। हमारी हवा सांस लेने लायक नही बची है। खेत और मिट्टी जहरीली हो चुकी है। अब हमें वायु प्रदूषण, गंदे ऊजां श्रोतों, रसायनिक खेती, डीजल वाहनों, ट्रैफिक समस्या, जीएम फसलों और कचरे से आजादी चाहिए। इसके निवारण के लिए सभी यही सोचते हैं कि कौन सबसे पहला कदम उठाए। सभी यह सोचते हैं कि हम इससे नही लड़ सकते लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनापतियों के आजादी के लड़ाई से सीख लें कि उस समय कुछ लोग यही सोचते थे कि क्या इतनी बड़ी हुकूमत को हराया जा सकता है। लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को गुलामी की जंजीर से आजादी करा दी। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को संकल्प लेना होगा और अपने कर्तव्य का पालन करना होगा।

आमतौर हम देश से अपेक्षाएं रखते हैं लेकिन खुद से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं ये जानते हुए भी हमसे ही बनता है देश। हम देश के लिए कुछ नही करते उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान नही करते और देश से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे लिए करे। हमसे ही देश बनता है। हमारे कार्यों से देश प्रगति के रास्ते पर जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के समय जरूर हम लोगों में देश के प्रति देश भक्ति उजागर होने लगती है। रेडियो, टेलीविजन में देशभक्ति के गाने हमें कुछ समय के लिए अपने कर्तव्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परन्तु कुछ समय के बाद हमारा मन भी और चीजों में उलझ जाता है। दरअसल व्यक्ति पांच स्तरों पर जीता है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा अद्ध्यात्मिक स्तरों पर। हर स्तर मे देश की एक प्रमुख भूमिका होती है। हम सब पर देश का उधार है। देश ने हमारी झोली में इतना कुछ दिया है फिर भी हम देश के सामने अपनी मांग ही रखते हैं।

कर्तव्यपालन के प्रति सतत जागरुकता से ही हम अपने अधिकारों का निरापद रखने वाले आजादी का पर्व सार्थक रूप से मना सकेंगे। तभी लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने का हमारा संकल्प साकार होगा। प्रायः कुछ से सुना जाता है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमें देश से कुछ नही मिला लेकिन क्या कुछ लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने देश को क्या दिया ? यदि सभी लोग याचना छोड़कर देश के प्रति अपने कर्त्तव्य निभाएं तो देश को उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन यह अधिकार तब तक अधूरा है जब तक देश के सामने मौजूद चुनौतियां को ख़त्म नहीं कर देते हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण। बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन आदि के कारण पृथ्वी पर संकट मंडराने लगा है।

पर्यावरण संरक्षण आज सबसे ज्यादा आवश्यक हो गया है। अकेले सरकार और नौकरशाहों का ही काम नहीं है बल्कि देश की प्रत्येक जनता को इसमें सहयोग देना होगा। आम लोग पर्यावरण के नुकसान से तो परिचित है लेकिन उन तौर तरीकों को रोकने के लिए सजग नही जो पर्यावरण को प्रदुषित कर रहे हैं। पर्यावरण अनमोल धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। युवाओं को तो इनके बारे में पता तक नहीं है। उन्हें जागरुक करने की जरूरत है। संविधान में अनु. 51 A (g) में भी उल्लेख किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव आदि भी हैं रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें। आजादी की सार्थकता तभी होगी जब हरेक व्यक्ति को काम, भोजन एवं स्वच्छ पर्यावरण मिले। संविधान में जो हमारे कर्तव्य तय किए गए हैं उसका हम सही ढंग से पालन करें तभी हमारा देश भी महान बनेगा। सबसे बड़ी बात अपने अपने मौलिक अधिकारों को पाहचाने ही साथ ही अपने मौलिक कर्तव्यों को भी निर्वहन करें। देशभक्ति का भाव किसी अवसर का मोहताज नहीं होता। यह हमारे भीतर का स्थाई भाव होना चाहिए। देशभक्ति का मतलब देश से अपेक्षा नहीं बल्कि देश के लिए देश के लिए कुछ करने की प्रवृति पैदा होना है।

तिरंगे की छांव में 80वां स्वतंत्रता दिवस

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

15 अगस्त 1947 केवल औपनिवेशिक शासन के अंत की तारीख नहीं है। यह सदियों के संघर्ष, असंख्य बलिदानों और करोड़ों भारतीयों की सामूहिक इच्छाशक्ति से अर्जित उस स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसने भारत को अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनाया। तिरंगा केवल हमारी संप्रभुता का प्रतीक नहीं, बल्कि अतीत के संघर्ष, वर्तमान के सामर्थ्य और भविष्य की आकांक्षाओं को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूत्र है। आज जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस और 79वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब स्वतंत्रता दिवस को केवल एक छुट्टी का अवसर मत समझिए। यह दिन है ठहरकर अपनी आजादी को महसूस करने का, उन बलिदानों को याद करने का जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र हैं। अपने आसपास जहां भी तिरंगा फहराया जा रहा हो, वहां जरूर पहुंचिए, राष्ट्रगान में शामिल होइए और स्वयं से एक सवाल पूछिए - जो भारत हमें हमारे पूर्वज सौंप गए, उसे और बेहतर बनाकर अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए हम क्या कर रहे हैं?

बलिदानों की नींव पर खड़ा भारत

भारत की स्वतंत्रता किसी एक आंदोलन, एक विचार अथवा एक व्यक्तित्व की देन नहीं थी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई तक देश के अलग-अलग हिस्सों, वर्गों और समुदायों से असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। किसी ने जेल की यातनाएं सहीं, किसी ने अपना परिवार छोड़ा और किसी ने हंसते-हंसते प्राण दे दिए। स्वतंत्र भारत की हर उपलब्धि के पीछे उस पीढ़ी का ऋण है, जिसने स्वयं से अधिक आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को महत्व दिया। आजादी के बाद चुनौती केवल देश को चलाने की नहीं थी, बल्कि इतनी विविधताओं वाले विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने की भी थी। संविधान ने लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के माध्यम से इस यात्रा को दिशा दी। दुनिया की आशंकाओं के बीच भारत ने लोकतंत्र को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी संस्थागत शक्तियों में बदल दिया।

अभाव से आत्मविश्वास तक

1947 का भारत अनेक चुनौतियों से घिरा था, विभाजन की पीड़ा, विस्थापन, गरीबी, खाद्यान्न संकट, सीमित औद्योगिक आधार और कमजोर बुनियादी ढांचा। इसके बावजूद हरित क्रांति ने खाद्यान्न सुरक्षा की दिशा बदली तो श्वेत क्रांति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी। बड़े बांध, उद्योग, शिक्षण संस्थान और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान आधुनिक भारत की नींव बने। समय के साथ आर्थिक सुधारों, उद्यमिता और तकनीकी बदलावों ने विकास की नई संभावनाएं खोलीं। भारत की वैज्ञानिक यात्रा तो इस बदलाव की सबसे प्रेरक तस्वीरों में से एक है। कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के उपकरण पहुंचाने वाला देश आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचने और सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता रखता है। यह यात्रा संसाधनों से कहीं अधिक संकल्प, प्रतिभा और आत्मविश्वास की कहानी है।

बदलती दुनिया में सामर्थ्यवान भारत

आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति, आधुनिक राजमार्ग, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डे और तेजी से बढ़ती कनेक्टिविटी नए भारत की गति और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। रक्षा से अंतरिक्ष तक, विज्ञान से चिकित्सा तक और खेल से उद्यमिता तक भारतीय प्रतिभा दुनिया में अपनी पहचान मजबूत कर रही है। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका भी लगातार बढ़ी है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सेना या तकनीक नहीं, बल्कि विविधताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की उसकी अद्भुत क्षमता है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक भाषा, पहनावा, भोजन और परंपराएं बदलती हैं, लेकिन भारत होने का भाव हमें एक सूत्र में बांधता है। दुनिया जब विभाजन और टकराव की चुनौतियों से जूझ रही है, तब हमारी अनेकता में एकता सह-अस्तित्व का सशक्त संदेश है।

आठ दशकों की यात्रा पर गर्व

आठ दशकों की इस यात्रा पर गर्व करते हुए यह भी याद रखना होगा कि राष्ट्र निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। स्वतंत्रता की सार्थकता तभी है, जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर युवा को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर, महिलाओं को समान भागीदारी और सुरक्षा, किसान को समृद्धि और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास में हिस्सेदारी मिले। हमें आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण, तकनीक के साथ मानवीय संवेदना और अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन साधना होगा। 2047 में भारत की सफलता केवल इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हुई, बल्कि इससे भी कि हमारा समाज कितना शिक्षित, स्वस्थ, न्यायपूर्ण, संवेदनशील और समावेशी बना।

अगली पीढ़ी को संवेदनशील भारत देना हमारी जिम्मेदारी

देश के प्रति हर जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है। शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, चिकित्सक संवेदनशीलता से उपचार करे, व्यापारी नैतिकता से कारोबार करे, किसान पूरी निष्ठा से अन्न उगाए, युवा नवाचार करे और नागरिक कानून, स्वच्छता तथा पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाए तो राष्ट्र मजबूत होता है। राष्ट्र हमसे अलग कोई सत्ता नहीं; हम सबका आचरण मिलकर ही राष्ट्र का चरित्र बनाता है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारा संकल्प केवल तिरंगा फहराने तक सीमित न रहे। जिन बलिदानों से हमें आजादी मिली, उनका सम्मान करने का सबसे सार्थक तरीका यही है कि हम भारत को उससे बेहतर बनाएं, जैसा हमें मिला था। आजादी हमें विरासत में मिली है; एक विकसित, समावेशी और संवेदनशील भारत अगली पीढ़ी को विरासत में देना हमारी जिम्मेदारी है।

जय हिंद! जय भारत!

जिनके अमर बलिदान से मिली स्वतंत्रता

उन वीरों को शत-शत नमन

नया मध्यप्रदेश

समानता का विश्वास, समावेशी विकास

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

"स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती, बल्कि यह कर्तव्य का स्मरण भी कराती है। आइए, हम सब मिलकर प्रदेश के समग्र विकास और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प लें।"

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रदेशवासियों को

80वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

जुड़ें नए मध्यप्रदेश से

R.O. No. : D18014/26

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)